

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2006.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 24 अगस्त, 2006/2 भाद्रपद, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 24 अगस्त, 2006

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्न० बिल/1-46/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायालय (द्वितीय

संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 21) जो आज दिनांक 24-8-2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव ।

2006 का विधेयक संख्यांक 21.

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 की धारा 21 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- धारा 21 का संशोधन।

“(1) जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय, सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) या सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) की डिक्री या आदेश की कोई अपील, मूल्यांकन को विचार में लाए बिना, जिला न्यायाधीश को होगी।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में, हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 की धारा 21 के अधीन सिविल न्यायाधीश की डिक्री या आदेश की अपील जिला न्यायाधीश को होती है, जहां मूल वाद का मूल्य जिसमें ऐसी डिक्री या आदेश किया गया था, दो लाख रुपये से अधिक नहीं है और अन्य मामलों में अपील माननीय उच्च न्यायालय को होती है। वर्तमानतः सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) और सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) उन समस्त मूलवादों में अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं जिनका मूल्य क्रमशः पांच लाख रुपये और दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, अधिसूचना द्वारा, नियत किया गया है, जहां मूल वाद, जिसमें डिक्री या आदेश सिविल न्यायाधीशों द्वारा किया गया है, का मूल्य दो लाख रुपये से अधिक है, वहां अपील माननीय उच्च न्यायालय को होती है और जिससे माननीय उच्च न्यायालय पर अनावश्यक भार पड़ता है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदेश में जिला न्यायाधीशों की अपीलीय अधिकारिता को बढ़ाने की बाबत मामले पर विचार किया है और राज्य सरकार को उपरोक्त अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) का प्रतिस्थापन प्रस्तावित करने हेतु संकल्प किया है। मामले पर विचार किया गया और धारा 21 को उपयुक्त रूप से संशोधित करने तथा जिला न्यायाधीशों की अपीलीय अधिकारिता को बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मंत्री।

शिमला:

तारीख:....., 2006

वित्तीय ज्ञापन

--शून्य--

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 21 of 2006.

**THE HIMACHAL PRADESH COURTS (SECOND AMENDMENT)
BILL, 2006**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Courts (Second Amendment) Act, 2006. Short title.

2. In section 21 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:— Amendment of section 21.

“(1) Save as aforesaid, any appeal from decree or order of Civil Judge (Senior Division) or Civil Judge (Junior Division) shall lie to the District Judge irrespective of the valuation.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present, an appeal from decree or order of a Civil Judge lies to the District Judge under section 21 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 where the value of the original suit in which such decree or order was made did not exceed 2 lacs rupees, and in other cases the appeal lies to the Hon'ble High Court. Presently Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division) are exercising jurisdiction in all original Civil Suit the value of which does not exceed Rupees 5 lacs and 2 lacs respectively as fixed by the Hon'ble High Court by notification. Where the value of original suit in which decree or order is made by Civil Judges exceeds Rupees 2 lacs, the appeal lies to the Hon'ble High Court and thereby putting unnecessary burden upon Hon'ble High Court. The Hon'ble High Court has considered the matter with regard to enhancement of appellate jurisdiction of District Judges in the Pradesh and resolved to move the State Government for substitution of sub-section(1) of section 21 of the Act *ibid*. The matter has been considered and it has been decided to amend section 21 suitably and to enhance the appellate jurisdiction of the District Judges. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

Shimla:

The, 2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—